

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Tuesday, 25 Feb, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 04 Syllabus : Prelims Fact	हमारा लक्ष्य 2029 तक 50,000 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात तक पहुंचना है: राजनाथ सिंह
Page 04 Syllabus : Prelims Fact	2024 में दुनिया भर में इंटरनेट शटडाउन सबसे ज्यादा होगा, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में भारत सबसे आगे
Page 07 Syllabus : Prelims Fact	अंतरिक्ष यात्रा किसी अंतरिक्ष यात्री के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है?
Page 07 Syllabus : GS 3 : Science and Technology	वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण की क्वान्टमनेस की जांच के लिए टेबलटॉप परीक्षण का प्रस्ताव रखा
Page 11 Syllabus : GS 2 : Governance	निगरानी पूंजीवाद: व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित करने की शक्ति
Page 08 : Editorial Analysis: Syllabus : GS 2 : Governance	आरटीआई अब 'सूचना से इनकार करने का अधिकार' बन गया है

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने रक्षा उत्पादन में 88% आत्मनिर्भरता और निर्यात में 23,000 करोड़ रुपये हासिल कर लिए हैं, जिसका लक्ष्य 2029 तक 50,000 करोड़ रुपये का है।

- उन्होंने उन विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला जिन पर सरकार काम कर रही है।

Our aim is to reach defence exports worth ₹50,000 crore by 2029, says Rajnath Singh

The Hindu Bureau
CHANDIGARH

Defence Minister Rajnath Singh on Monday said India had achieved 88% self-sufficiency in ammunition production, and defence exports had reached about ₹23,000 crore in 2023-24.

He was speaking at the 16th Foundation Day of the Indian Institute of Technology, Mandi in Himachal Pradesh.

“Our goal is to reach ₹50,000 crore in defence exports by 2029,” Mr. Singh said.

Economic growth

The Minister said the government was committed to creating a robust defence industry in India, which supported the security of the nation and contributed to the country's economic growth.

He called upon IIT-Mandi students to contribute to this vision by focusing on technological solutions that would enhance India's defence capabilities and



Rajnath Singh

further advance the nation's self-reliance in this critical sector.

Emphasising the necessity of innovation and knowledge-creation in shaping the future of technology, Mr. Singh underscored the importance of fostering a culture of entrepreneurship and innovation that would allow India to lead in emerging fields, including artificial intelligence, machine learning, and digital technologies.

He asked the students to excel in technological innovation in order to make India a developed country by 2047, and advised them to follow the principles of

“initiate, improve, and transform (IIT)”.

“India's technological sector is on the rise and is expected to reach \$300-350 billion dollars in the next five years. With more than 1.25 lakh start-ups and 110 unicorns, our country is emerging as the third-largest startup ecosystem in the world,” Mr. Singh said.

Digital economy

The Defence Minister highlighted India's digital economy.

“India's telecom sector is now the second-largest in the world. With the success of initiatives like UPI (Unified Payments Interface), India is setting global standards in digital transactions. We are in the midst of an unparalleled digital revolution. The students should actively contribute to the development of India's digital ecosystem as technological innovation is central to India's growth story in the coming decades,” Mr. Singh said.

रक्षा उत्पादन और निर्यात में उपलब्धि

- ▶ भारत ने गोला-बारूद उत्पादन में **88%** आत्मनिर्भरता हासिल की है।
- ▶ रक्षा निर्यात **2023-24** में **₹23,000** करोड़ तक पहुँच गया है।
- ▶ सरकार का लक्ष्य **2029** तक रक्षा निर्यात को **₹50,000** करोड़ तक बढ़ाना है।

रक्षा उद्योग को मज़बूत बनाना

- ▶ सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए एक मज़बूत रक्षा उद्योग बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
- ▶ छात्रों, विशेष रूप से तकनीकी संस्थानों से, को रक्षा नवाचार और आत्मनिर्भरता में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

नवाचार और उद्यमिता का महत्व

- ▶ नवाचार और ज्ञान सृजन भारत के तकनीकी नेतृत्व की कुंजी है।
- ▶ सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डिजिटल तकनीकों में प्रगति को बढ़ावा देती है।
- ▶ छात्रों को बदलाव और प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए “आरंभ करें, सुधारें और बदलाव करें (IIT)” के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए।

भारत का बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम

- ▶ भारत में **1.25** लाख से ज़्यादा स्टार्टअप और **110** यूनिคอร์न के साथ एक समृद्ध स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
- ▶ देश वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है।
- ▶ भारत में तकनीकी क्षेत्र के अगले पाँच सालों में **300-350** बिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है।

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास

- ▶ भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार क्षेत्र है।
- ▶ **UPI** (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस) की सफलता ने भारत को डिजिटल लेन-देन में वैश्विक नेता बना दिया है।
- ▶ एक डिजिटल क्रांति चल रही है, और छात्रों को दीर्घकालिक विकास के लिए भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

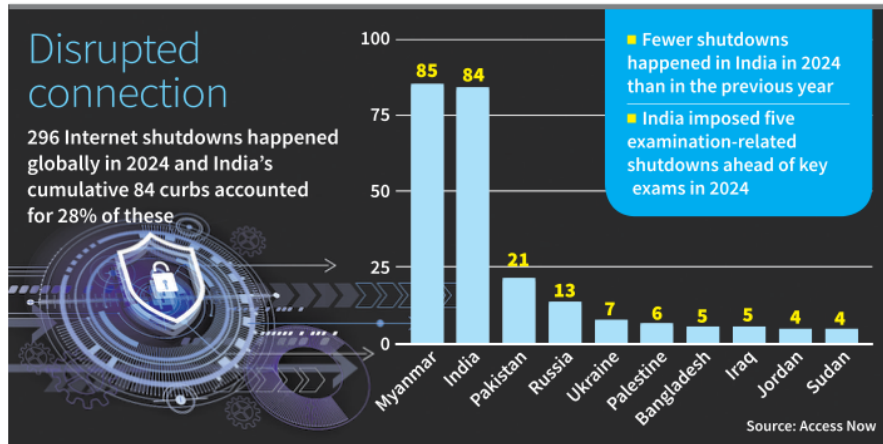
- ➔ एक्सेस नाउ की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में दुनिया भर में 296 बार इंटरनेट बंद हुआ, जो किसी भी वर्ष में दर्ज की गई सबसे अधिक संख्या है।

Internet shutdowns highest in 2024 globally, India tops in government-ordered curbs

Aroon Deep
NEW DELHI

India did not impose the highest number of Internet shutdowns last year, with Myanmar seeing one additional disruption in 2024, according to a report by the advocacy body Access Now. However, the number of shutdowns imposed by the government in charge – the Union and State governments here – is still higher in India.

Fewer shutdowns happened in India in 2024 than in the previous year. "People in 16 States and [Union] Territories experienced a shutdown, with State Government officials in Manipur (21), Haryana (12), and Jammu & Kashmir (12) topping the list of offenders in India," the report said.



"Of the 84, 41 shutdowns were related to protests, and 23 were related to communal violence."

More shutdowns happened globally in 2024 than in any past year.

In all, 296 Internet shutdowns happened globally in 2024, the report found,

and India's cumulative 84 curbs accounted for 28% of these. Eighty-five were imposed in Myanmar, and 11 of these were a result of other countries and groups: "China imposed two [shutdowns on areas in Myanmar] and Thailand four, while the exiled Na-

tional Unity Government (NUG), Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA), and Ta'ang National Liberation Army (TNLA) imposed one shutdown each in areas they controlled. The remaining two shutdowns were imposed by unknown par-

ties," the report said.

A particular focus of anti-shutdown advocates' ire has been examination-related shutdowns. India imposed five such shutdowns ahead of key exams in 2024. One was during the General Graduate Level Combined Competitive Examinations in Jharkhand, which took place for five-and-a-half hours from September 22 morning through the afternoon.

That same month, Assam imposed similar shutdowns in most districts for government job exams.

Rajasthan issued a shutdown for the Rajasthan Public Service Commission exam in January. Exam-related Internet shutdowns are a disproportionate response to the possibility of cheating in exams, Access Now said.

- ➔ रिपोर्ट का शीर्षक है "अपराधियों का हौसला बढ़ाना, संकटग्रस्त समुदाय: 2024 में इंटरनेट शटडाउन।"

भारत-विशिष्ट शटडाउन

- ➔ भारत ने 84 बार इंटरनेट शटडाउन लगाया, जो वैश्विक मामलों का 28% है।
- ➔ म्यांमार में सबसे ज़्यादा शटडाउन (85) हुए, जिनमें से कुछ बाहरी देशों और सशस्त्र समूहों द्वारा लगाए गए थे।

भारतीय राज्यों में शटडाउन

- ➔ भारत में इंटरनेट शटडाउन ने 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावित किया।
- ➔ सबसे ज़्यादा शटडाउन मणिपुर (21), हरियाणा (12) और जम्मू और कश्मीर (12) में हुए।
- ➔ 84 शटडाउन में से 41 विरोध प्रदर्शनों से जुड़े थे और 23 सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े थे।

Page 07 : Prelims Fact

- ▶ अंतरिक्ष यात्रा सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, विकिरण जोखिम और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों के कारण अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।

अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियाँ

- ▶ मानव शरीर अंतरिक्ष यात्रा के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, जहाँ सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और विकिरण जोखिम विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं।
- ▶ अंतरिक्ष यात्रियों को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर लंबी अवधि के मिशनों पर।
- ▶ सुरक्षात्मक उपाय और व्यक्तिगत स्वास्थ्य रणनीतियाँ विकसित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है।

विकिरण जोखिम जोखिम

- ▶ पृथ्वी का वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र मनुष्यों को अंतरिक्ष विकिरण से बचाता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में इस सुरक्षा की कमी होती है।
- ▶ उच्च-ऊर्जा विकिरण जोखिम डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है, कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित कर सकता है।
- ▶ लंबे समय तक जोखिम के कारण न्यूरोडीजेनेरेटिव प्रभाव हो सकते हैं।
- ▶ निम्न-पृथ्वी कक्षा मिशन कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन चंद्रमा जैसे गहरे अंतरिक्ष मिशनों में उच्च विकिरण खुराक शामिल होती है।

सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव

- ▶ गुरुत्वाकर्षण शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करता है, और इसकी अनुपस्थिति द्रव शिफ्ट का कारण बनती है, जिससे इंटरक्रैनील दबाव और दृष्टि संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं।
- ▶ मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ घनत्व खो देती हैं, और हृदय प्रणाली रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करती है।
- ▶ आंतरिक कान अपनी हरकतों को महसूस करने की क्षमता खो देता है, जिससे संतुलन और समन्वय संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं।

मनोवैज्ञानिक प्रभाव

- ▶ सीमित सामाजिक संपर्क के साथ बंद जगहों पर रहने से तनाव, नींद की समस्या और मूड संबंधी विकार हो सकते हैं।

अंतरिक्ष उड़ान के बाद रिकवरी



Long-duration missions require astronauts to live in confined and isolated environments. REUTERS

How does space travel affect health of an astronaut?

Reuters

The human body was not built for spaceflight, with its microgravity conditions, exposure to high-energy radiation, and other issues. As a result, trekking beyond the earth's confines causes many physiological changes that affect an astronaut's health. Space travel exposes people to an environment different from the earth's, posing a range of physiological and psychological challenges, especially with prolonged exposure, according to Afshin Beheshti, director of the Centre for Space Biomedicine at the University of Pittsburgh. As researchers seek new countermeasures to protect space travellers, more data is needed on astronauts with varying health backgrounds and undertaking different kinds of missions in order to map out personalised risk profiles and mitigation

Space travel exposes people to a different environment, posing physiological and psychological challenges, especially with prolonged exposure

strategies, Chris Mason, a professor of physiology and biophysics at Weill Cornell Medicine in New York, said. Unlike on the earth, where the atmosphere and planetary magnetic field provide a shield from space radiation, astronauts are exposed to high-energy radiation permeating the cosmos. This can lead to DNA damage, increased cancer risk, neurodegenerative effects and immune system dysregulation. The earth's magnetosphere provides some protection for astronauts in missions in low-earth orbit. But astronauts traveling beyond that, such as on missions to the moon, would experience much higher radiation doses. Gravity plays a critical role in regulating bodily functions. Without gravity, bodily fluids shift upward, increasing intracranial pressure that can affect vision. The lack of mechanical loading on bones and muscles associated also leads to bone density loss and muscle atrophy. The cardiovascular system also changes, struggling to regulate blood pressure upon return. Prolonged exposure to microgravity conditions also affects the inner ear's ability to sense movement and orientation, leading to balance and coordination issues. Long-duration space missions require astronauts to live in confined and isolated environments with limited social interaction and exposure to natural stimuli. This, Beheshti said, can lead to psychological stress, sleep disturbances, and mood disorders. How astronauts recover after returning to the earth depends mostly on mission duration. For short-duration missions of a few days in low-earth orbit, about 95% of biological damage sustained appears to be reversed. For astronauts who spend months aboard the International Space Station, recovery appears proportional to their time in space. Many physiological systems gradually return to normal. But some issues persist. For example, spaceflight-associated neuro-ocular syndrome has been linked to impaired vision due to microgravity-induced fluid shifts and changes in intracranial pressure affecting the eyes.

Daily News Analysis

- ▶ छोटे मिशनों में **95%** जैविक रिकवरी होती है, लेकिन लंबे मिशनों के लिए लंबे समय तक पुनर्वास की आवश्यकता होती है।
- ▶ कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जैसे दृष्टि दोष, पृथ्वी पर लौटने के बाद भी बनी रह सकती हैं।



वैज्ञानिक इस बात की खोज कर रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्वांटम यांत्रिकी का अनुसरण करता है या नहीं, इसके लिए वे इसके सुपरपोजिशन और उलझाव का परीक्षण करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं।

► यदि यह सिद्ध हो जाता है, तो इससे गुरुत्वाकर्षण को अन्य मूलभूत बलों के साथ एकीकृत करने में मदद मिल सकती है।

Scientists propose tabletop test to check quantumness of gravity

Unlike Newtonian mechanics, where measuring a system doesn't alter it, quantum mechanics dictates that observing a system forces it into a definite state; this difference creates a way to test whether the system is behaving according to the laws of Newtonian or quantum mechanics

Debdutta Paul
BENGALURU

General relativity and quantum mechanics are two highly successful theories. The former explains gravity and the latter teams up with special relativity to describe the other three forces of nature: electromagnetic, strong nuclear, and weak nuclear forces.

However, scientists don't know how gravity fits into quantum mechanics. In fact, they have been proposing experiments that can test the quantumness of gravity. On October 29, 2024, one such proposal appeared in the journal *Physical Review Letters*.

With concepts like superposition, illustrated by the Schrödinger's cat thought experiment, and entanglement, quantum mechanics defies classical intuition. Quantum mechanics also allows seemingly absurd phenomena, e.g. the measurement of a quantum system (like a particle) can cause the system to instantaneously 'collapse' into one possible state that described the system before the measurement.

In fact, if a system undergoes measurement-induced collapse, it's said to live by the rules of quantum mechanics. Classical systems like planets orbiting stars, cricket balls flying in the air, and cars on the road don't do this.

Ruling out alternatives

Multiple experiments have found that both quantum mechanics and general relativity are legitimate theories of nature – yet they remain incompatible with each other. This has encouraged physicists to try and come up with a larger theory that can accommodate both. One strong contender is string theory, another is loop quantum gravity. Both of them predict deviations from quantum mechanics and general relativity either at the beginning of the universe or inside black holes, meaning they're nearly impossible to test.

"So far, experimental tests are extremely difficult – the situation looks very bleak – it is not clear if it can be done at all," Dipankar Home of Bose Institute, Kolkata, and one of the authors of the new paper, said.

To check whether gravity is quantum mechanical, scientists need precise tests that rule out alternative possibilities.

Unlike the classical Newtonian mechanics, where measuring a system doesn't alter it, quantum mechanics dictates that observing a system forces it into a definite state. This isn't a matter of how carefully a physicist is making the measurement. The measurement will always collapse the state. So measuring the state versus not measuring it creates a way to test whether the system is behaving according to the laws of Newtonian mechanics or quantum mechanics.

As a first step, physicists said they needed an experiment where gravity helps an inherently quantum mechanical process happen. If gravity causes the state to collapse, it will be a sign that gravity behaves quantum mechanically.

The new study suggested the following design: a test mass is in a superposition of two possible paths it can take. A probe mass will interact with it gravitationally to force it to choose one of the paths. Here, both masses are in a superposition of which paths they take. These two paths



If a system undergoes measurement-induced collapse, it is said to live by the rules of quantum mechanics. Classical systems like falling apples or planets orbiting stars don't do this. Representative image. unplash

come close, resulting in different distances between the two pairs of paths. That is, for each path of the test mass, there are two possible paths the probe mass can take.

"Such simple, yet novel proposals ... are very interesting to the community," said Sreenath K. Manikandan, a theoretical physicist at the Nordic Institute for Theoretical Physics, Sweden, who wasn't involved in the study.

Testing weak gravity

The idea is also interesting because it proposes to test weak gravity. Say you're performing an experiment where you're looking for light. If the light is bright, you can find it just by looking at it. But if it is very dim, you need sophisticated light-detecting cameras. Similarly, ideas to look for quantum gravity have so far involved strong gravity, like that near black holes, whereas the new test proposes looking for weak gravity, like the force near a small object.

"Our contention is that fundamental quantum gravity features can persist in this limit," Home said. Igor Pikovski, a quantum gravity researcher at the Stevens Institute of Technology and Stockholm University, commended this. "The important lesson is that quantum gravity signatures might show themselves even ... in tabletop set-ups and not just in science-fiction scenarios."

But independent experts said the experiment is still challenging because the masses need to behave quantum mechanically.

Quantum properties usually show up at a smaller than microscopic scale, like inside atoms, whereas gravity is easier to

Experiments have found both quantum mechanics and general relativity are legitimate theories, yet they remain incompatible with each other, encouraging physicists to search for a larger theory to accommodate both

measure around larger objects, like a building. This is why Vivesh Sudhir of the Massachusetts Institute of Technology said, "Preparing a spatial quantum superposition of an object massive enough such that its gravitational force is also measurable is an enormous experimental challenge."

Creating a superposition

Bose et al. have proposed the use of masses weighing about one-trillionth of a gram while maintaining a separation of around one-tenth of a millimetre. Nanocrystals meet these criteria.

Yet the team still estimates a decade for their experiment to be conducted. Thus far, "the largest objects that have been placed in two places at once are macromolecules. We will have to place a nanocrystal, which is a billion times larger, in two places at once," Sougato Bose, one of the coauthors of the study, said.

"Creating this superposition is by far the main challenge," Debarshi Das, another coauthor, added.

To do so, the authors have proposed using a quantum property of the nanocrystals called spin. Simply speaking, the spin affects the nanocrystals' motion (and can be manipulated by an external magnetic field). The spin of each nanocrystal exists in a superposition of

two states until it is measured. Since the state affects the nanocrystal's path, it also exists in a superposition of two paths until a measurement.

"Once prepared in such a state, the gravitational field produced by this configuration will need to be measured very rapidly," according to Sudhir. "This is because any spatial quantum superposition will be extremely fragile and will die quickly, [so] measurements have to be made before this happens."

Bose also said the nanocrystals can collide with gas atoms and other objects and forces in their environment, which could destroy the superposition. "This could include things like the gravitational forces from seismic activity in the earth or perhaps even those due to clouds moving in the sky," Sudhir said.

For these reasons, the experimental set-up will have to happen in a near-perfect vacuum and the masses' properties will have to be measured with extreme efficiency.

Despite all these challenges, physicists are hopeful. The proposed test has a much shorter timeline than the centuries required for humankind to develop the technologies to test quantum gravity near black holes.

Pikovski agreed the future is bright: "Just a few years ago, it was considered impossible to experimentally test quantum gravity even in principle."

The experts also said that the test may reveal gravity isn't a classical force, and that overall they will have to keep an open mind: it may not necessarily mean gravity is quantum but that it could be a non-classical and non-quantum entity, something different altogether.

(Debdutta Paul is a freelance science journalist. ddbtpt@gmail.com)

सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी के बीच संघर्ष

- ▶ सामान्य सापेक्षता गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या करती है, जबकि क्वांटम यांत्रिकी अन्य तीन मूलभूत बलों की व्याख्या करती है।
- ▶ वैज्ञानिकों को अभी तक नहीं पता है कि गुरुत्वाकर्षण क्वांटम यांत्रिकी में कैसे फिट बैठता है।
- ▶ यह जांचने के लिए प्रयोगों की आवश्यकता है कि गुरुत्वाकर्षण क्वांटम नियमों के अनुसार व्यवहार करता है या नहीं।

क्वांटम यांत्रिकी की अवधारणाएँ

- ▶ क्वांटम यांत्रिकी में सुपरपोजिशन और उलझाव जैसे सिद्धांत शामिल हैं, जो शास्त्रीय भौतिकी को चुनौती देते हैं।
- ▶ मापने पर एक क्वांटम प्रणाली शास्त्रीय प्रणालियों के विपरीत एक निश्चित अवस्था में ढह जाती है।
- ▶ यदि गुरुत्वाकर्षण क्वांटम नियमों का पालन करता है, तो इसे मापने से इसकी अवस्था ढह जानी चाहिए।

गुरुत्वाकर्षण की क्वांटम प्रकृति

- ▶ गुरुत्वाकर्षण क्वांटम यांत्रिकी के नियमों का पालन कर सकता है। इसका मतलब है कि यह एक सहज बल के बजाय छोटे कणों की तरह काम कर सकता है।
- ▶ क्वांटम यांत्रिकी में, कण एक साथ दो अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं। इसे सुपरपोजिशन कहा जाता है।
- ▶ यदि गुरुत्वाकर्षण क्वांटम है, तो इसे सुपरपोजिशन और उलझाव भी दिखाना चाहिए। इसका मतलब है कि दो वस्तुएं जुड़ी हो सकती हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हों।
- ▶ वैज्ञानिक यह जांचना चाहते हैं कि क्या गुरुत्वाकर्षण इस तरह व्यवहार करता है।
- ▶ यदि यह सत्य है, तो यह भौतिकी को एकीकृत करने में मदद कर सकता है। यह गुरुत्वाकर्षण को प्रकृति में अन्य बलों से जोड़ेगा।

क्वांटम गुरुत्वाकर्षण का परीक्षण करने के लिए प्रस्तावित प्रयोग

- ▶ वैज्ञानिक दो पथों के सुपरपोजिशन में एक परीक्षण द्रव्यमान का उपयोग करके एक प्रयोग का सुझाव देते हैं।
- ▶ एक जांच द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण के साथ बातचीत करेगा, इसे एक पथ में मजबूर करेगा।
- ▶ यदि गुरुत्वाकर्षण इस पतन का कारण बनता है, तो यह संकेत दे सकता है कि गुरुत्वाकर्षण प्रकृति में क्वांटम है।

कमज़ोर गुरुत्वाकर्षण का परीक्षण

- ▶ इस प्रयोग का उद्देश्य कमज़ोर गुरुत्वाकर्षण प्रभावों का परीक्षण करना है, जिससे यह अधिक व्यवहार्य हो सके।
- ▶ यदि सफल रहा, तो टेबलटॉप प्रयोगों में क्वांटम गुरुत्वाकर्षण प्रभाव देखे जा सकते हैं।

चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ

- ▶ इस प्रयोग के लिए एक नैनोकृस्टल, एक खरब ग्राम, को सुपरपोजिशन में रखना आवश्यक है।
- ▶ हस्तक्षेप को रोकने के लिए सेट-अप लगभग पूर्ण वैक्यूम में होना चाहिए।
- ▶ चुनौतियों के बावजूद, वैज्ञानिकों का मानना है कि क्वांटम गुरुत्वाकर्षण का परीक्षण अब एक दशक के भीतर संभव है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के उदय ने निगरानी पूंजीवाद को जन्म दिया है, जहाँ व्यक्तिगत डेटा निकाला जाता है और उसका मुद्रीकरण किया जाता है।

➔ इससे गोपनीयता, स्वायत्तता और कॉर्पोरेट नियंत्रण को लेकर चिंताएँ पैदा होती हैं।

Surveillance capitalism: the power to control personal data

A look at how surveillance capitalism relies on the commodification of personal data; its impact on privacy and autonomy; and its deep ties to state surveillance

Rebecca Rose Varghese

A was chatting with B and C in a social media group about an upcoming wedding she was attending. She casually mentioned needing a new dress and some accessories. Later that evening, as she scrolled through her social media feed, she was bombarded with advertisements for dresses, shoes, and jewellery – precisely like the ones she had described. Have you ever experienced this? And if you have, do you wonder how and why this happens, and whether your private conversations can be accessed by some other entity?

In simple terms, this is exactly what happens under surveillance capitalism. Surveillance capitalism is an economic system in which personal data is collected, analysed, and sold by tech conglomerates to predict and manipulate human behaviour. This system is so integral to the digital economy that it has reshaped capitalism itself, as American author and professor Shoshana Zuboff argues in her 2018 book *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. She describes surveillance capitalism as a new economic order that expropriates human experience for data-driven profit, and compares it to earlier exploitative systems like colonialism and industrial capitalism.

The concept

Unlike traditional capitalism, which revolves around goods and services, surveillance capitalism extracts human experience as raw material to mine data, predict behaviour, and influence decisions. This data is sold to advertisers, political campaigns, and other entities. Companies like Google, Meta, and Amazon have turned the internet into a vast surveillance machine, tracking and monetising every click, search, purchase, and in some cases even offline movements.

Zuboff describes the power from extensive data collection as instrumental power – control that does not rely on coercion but which subtly shapes behaviour. This is achieved through predictive analytics, recommendation algorithms, and targeted content, nudging individuals towards actions that benefit corporations. Alex Pentland's concept of social physics further illustrates how analysing vast datasets of human interactions reveals patterns, allowing corporations and policymakers to model, predict, and influence collective behaviour. This makes individuals more predictable economic actors, reinforcing surveillance capitalism's role in shaping consumer choices and social trends while prioritising profit over autonomy.

Different from past forms

Surveillance capitalism differs fundamentally from industrial capitalism. While industrial capitalism relies on labour and material production, surveillance capitalism profits from behavioural data extraction. Instead of tangible goods, companies commodify human experience, making users both consumers and raw material for



GETTY IMAGES

data-driven predictions.

Under industrial capitalism, companies focus on efficiency, productivity, and the exploitation and control of labour in manufacturing. Surveillance capitalism, however, is about controlling behaviour. Algorithms keep users engaged and guide them toward choices that benefit tech giants. This system prioritises data collection over autonomy, making every interaction a chance for monetisation.

One of the most concerning aspects of surveillance capitalism is its entanglement with state surveillance. Governments increasingly rely on private tech companies for intelligence gathering, policing, and social control. Instead of developing independent surveillance infrastructures, states now have access to

vast amounts of privately collected data, which they can obtain through legal means such as data-sharing agreements or extra-legal methods. The collaboration between corporations and states creates a system where the private sector's profit motives and public security interests align, at the expense of individual privacy and civil liberties. This reduces democratic accountability, as much of this surveillance happens within private corporations, beyond public scrutiny. Policies that favour deregulation and corporate autonomy allow this model to persist with minimal oversight, reinforcing a structure where both states and corporations benefit from mass surveillance while individuals face increasing risks of data exploitation and

loss of autonomy.

Eroding autonomy

Surveillance capitalism's reliance on extensive data collection has created a fragile and interconnected digital network. The sheer volume of data flowing through corporate and state surveillance systems mean that disruptions in one area can lead to cascading failures across multiple sectors. This systemic fragility becomes evident during major data breaches and algorithmic failures, which have led to real-world consequences such as financial instability and misinformation crises.

A notable example is the Cambridge Analytica scandal, where vast amounts of Facebook user data were harvested without consent in 2014, and used to build a system that could target voters in the U.S. with personalised political advertisements. This demonstrated how personal data, when exploited, can influence democratic processes, reinforcing concerns over the unchecked power of surveillance capitalism.

The pervasive data monitoring and predictive analytics employed by corporations further erode personal autonomy. Every action online is recorded, analysed, and used to refine behavioural predictions. Over time, users are subtly conditioned by algorithmic content, influencing their preferences and decisions in ways that serve the interests of advertisers and tech corporations rather than their own. While this seems harmless, it slowly erodes autonomy, allowing those in power to shape individual thinking for their benefit.

Challenges in regulation

Despite growing awareness of the dangers of surveillance capitalism, regulatory frameworks struggle to keep pace with technological advancements. Laws such as the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR) and India's Digital Personal Data Protection Act (DPDPA) attempt to give users more control over their data. However, these regulations fail to address the core issue – the commodification of personal information. This is largely because existing legal frameworks are designed to manage data privacy within traditional capitalist models rather than protect individuals from the structural impact of surveillance capitalism.

Moreover, corporate lobbying and political interests, particularly those in power, bungle these efforts as surveillance capitalism is highly beneficial for them. The rise of tech leaders as politicians is also an example of the interplay between surveillance capitalism and the surveillance state. When tech giants gain increasing influence over policymaking, they ensure that regulations remain favourable to their business interests. This dynamic makes it difficult to implement meaningful restrictions on data collection and behavioural manipulation. The blurred lines between political authority and corporate power reinforce the dominance of surveillance capitalism, limiting accountability and individual autonomy.

The concept of surveillance capitalism is crucial as our lives become increasingly entangled with technology. It serves as a warning of the potential dangers if we are not cautious and if states fail to implement proper regulations and restrictions on what private companies can access and use. This is an academic concept that must be widely discussed to bring about meaningful policy changes. Recognising its impact enables individuals to critically engage with digital platforms and demand stronger protections for their privacy and autonomy.

Rebecca Rose Varghese is a freelance journalist.

निगरानी पूंजीवाद को समझना

- निगरानी पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है, जिसमें कंपनियां मानव व्यवहार की भविष्यवाणी करने और उसे प्रभावित करने के लिए व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं, उसका विश्लेषण करती हैं और उसे बेचती हैं।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टेक कंपनियां ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करती हैं और लक्षित विज्ञापनों और सामग्री अनुशंसाओं के लिए डेटा का उपयोग करती हैं।
- इस प्रणाली ने मानव अनुभव को लाभ का स्रोत बनाकर पूंजीवाद को नया रूप दिया है।
- पारंपरिक पूंजीवाद के विपरीत, जो वस्तुओं और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, निगरानी पूंजीवाद लाभ कमाने के लिए व्यवहार संबंधी डेटा निकालता है।
- कंपनियां इस डेटा का उपयोग विस्तृत उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल बनाने और उन्हें विज्ञापनदाताओं, राजनीतिक अभियानों और व्यवसायों को बेचने के लिए करती हैं।

इंस्ट्रुमेंटैरियन पावर और व्यवहार नियंत्रण

- निगरानी पूंजीवाद बल पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि व्यवहार को प्रभावित करने के लिए भविष्य कहनेवाला विश्लेषण और अनुशंसा एल्गोरिदम का उपयोग करता है।
- व्यक्तिगत विज्ञापन, समाचार फ़ीड और वीडियो सुझाव उपयोगकर्ताओं को कुछ निश्चित कार्यों की ओर निर्देशित करते हैं, अक्सर उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता।
- नियंत्रण का यह स्तर लोगों को अधिक पूर्वानुमानित आर्थिक अभिनेता बनाता है, जिससे व्यक्तिगत स्वायत्तता की कीमत पर निगमों को लाभ होता है।

औद्योगिक पूंजीवाद के साथ तुलना

- औद्योगिक पूंजीवाद भौतिक वस्तुओं और श्रम पर केंद्रित था, जबकि निगरानी पूंजीवाद मानव अनुभव और ऑनलाइन गतिविधि से लाभ कमाता है।
- औद्योगिक पूंजीवाद में, दक्षता और उत्पादकता महत्वपूर्ण थी, लेकिन निगरानी पूंजीवाद का उद्देश्य अधिकतम लाभ के लिए उपयोगकर्ता की सहभागिता को नियंत्रित करना है।
- एल्गोरिदम उपयोगकर्ताओं को लंबे समय तक ऑनलाइन रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे डेटा संग्रह और विज्ञापन राजस्व में वृद्धि होती है।

सरकारों की भागीदारी

- सरकारें सुरक्षा और खुफिया उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा तक पहुँचने के लिए तकनीकी कंपनियों के साथ सहयोग करती हैं।
- स्वतंत्र निगरानी नेटवर्क बनाने के बजाय, अधिकारी कानूनी और गैर-कानूनी तरीकों से निजी कंपनियों से डेटा प्राप्त करते हैं।
- यह साझेदारी गोपनीयता के बारे में चिंताएँ बढ़ाती है, क्योंकि कॉर्पोरेट और राज्य के हित संरेखित होते हैं, जिससे सार्वजनिक जवाबदेही कम होती है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा

- निगरानी पूंजीवाद एल्गोरिदम हेरफेर के माध्यम से लोगों की प्राथमिकताओं और विकल्पों को कंडीशनिंग करके व्यक्तिगत स्वायत्तता को कमजोर करता है।

Daily News Analysis

- निरंतर निगरानी और डेटा संग्रह सूक्ष्म तरीकों से निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं, अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता देते हैं।
- राजनीतिक विज्ञापन के लिए सोशल मीडिया डेटा के 2014 के दुरुपयोग से पता चला कि लोकतांत्रिक परिणामों को आकार देने के लिए व्यक्तिगत डेटा का कैसे शोषण किया जा सकता है।

विनियामक चुनौतियाँ

- यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (जीडीपीआर) और भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपीए) जैसे कानून डेटा गोपनीयता को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं।
- हालाँकि, ये विनियमन व्यक्तिगत जानकारी को वस्तु में बदलने की मूल प्रथा को नहीं रोकते हैं।
- तकनीकी कंपनियाँ और राजनीतिक नेता अक्सर सख्त विनियमन का विरोध करते हैं, क्योंकि निगरानी पूंजीवाद से उन्हें आर्थिक और राजनीतिक रूप से लाभ होता है।

जागरूकता और नीतिगत बदलावों की आवश्यकता

- जैसे-जैसे तकनीक दैनिक जीवन में अधिक एकीकृत होती जाती है, निगरानी पूंजीवाद के जोखिमों को संबोधित किया जाना चाहिए।
- गोपनीयता की रक्षा और अत्यधिक कॉर्पोरेट नियंत्रण को रोकने के लिए मजबूत कानूनों और बेहतर निगरानी की आवश्यकता है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: निगरानी पूंजीवाद की अवधारणा और गोपनीयता, लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए इसके निहितार्थों पर चर्चा करें। इस उभरते आर्थिक मॉडल को विनियमित करने के उपाय सुझाएँ। (250 Words /15 marks)

The RTI is now the 'right to deny information'

The introduction of the Right to Information (RTI) Act was a move that generated great hope among citizens since it recognised them to be the rulers of the nation. It empowered them to seek information from the government, with dignity and respect. It looked as if the 'swaraj' that they had missed would be delivered to them. The Act codified their fundamental right to information and was one of the best transparency laws in the world. It appeared that it would curb corruption and arbitrariness, with citizens being the vigilance monitors of their government. But, it must be conceded, it has fallen far short of our expectations and the state of our democracy is not better.

Within a few months, the government realised that this was a transfer of power from public servants to the citizens. In less than a year it moved to amend the law which would have weakened the RTI Act. But there were widespread protests by citizens across the nation. Sensing the mood of the nation, the government dropped the amendments.

A gradual erosion

The RTI Act had created Information Commissions as the final appellate authorities to implement the law. Most of the posts of 'information commissioner' were taken up by retired bureaucrats. After working for decades as senior bureaucrats, it was difficult for them to hand over power to citizens and recognise that they were the rightful owners of the government. No attempt was made to select people with a record in transparency. Many of them looked at these jobs as post-retirement sinecures and worked only for a few hours. While the national average of the disposal of cases by High Court judges is over 2,500 in a year, the national average of disposal of cases by the commissioners was less than this. Given the fact that the complexity of cases before commissions is far less than the cases before the High Courts, each commissioner should have been clearing at least over 5,000 cases in a year. While the law mandated a period of 30 days for the information to be provided and the same period for the first appellate authorities, it did not specify any time limit for the commissioners. Many commissions began to have pendency of over a year. The right to information was being converted into a right to history. Many ordinary citizens could not pursue the issue of what was now a denial of information. The penal provisions of the RTI Act were the teeth of the Act, but most information commissioners were reluctant to use them. The governments delayed appointing commissioners, which only increased the backlogs.

The clear message of various High Court



Shailesh Gandhi

is a former Central Information Commissioner

Citizens and the media must take up the responsibility to ensure that the original RTI Act is followed and not allow any distortions

judgments was that the exemptions listed under Section 8 of the RTI Act were restrictions on a citizen's fundamental right and had to be construed strictly as in the law. Parliament intended most information to be provided and crafted the exemptions carefully.

The entire approach to a citizen's right to information changed in August 2011 when the Supreme Court of India held in *Central Board of Secondary Education & Anr. vs Aditya Bandopadhyay & Ors.*, in paragraph 33: "Some High Courts have held that section 8 of RTI Act is in the nature of an exception to section 3 which empowers the citizens with the right to information, which is a derivative from the freedom of speech; and that therefore section 8 should be construed strictly, literally and narrowly. This may not be the correct approach."

In paragraph 37 it made a comment without any evidence: "Indiscriminate and impractical demands or directions under RTI Act for disclosure of all and sundry information (unrelated to transparency and accountability in the functioning of public authorities and eradication of corruption) would be counterproductive as it will adversely affect the efficiency of the administration and result in the executive getting bogged down with the non-productive work of collecting and furnishing information. The Act should not be allowed to be misused or abused, to become a tool to obstruct the national development and integration, or to destroy the peace, tranquility and harmony among its citizens. Nor should it be converted into a tool of oppression or intimidation of honest officials striving to do their duty."

This justified treating RTI as an undesirable activity and labelling RTI users as outcasts. It justified not giving information and attacks on RTI users.

The subject of 'personal information'

The second major blow came with the judgment in *Girish Ramchandra Deshpande vs Cen. Information Commr. & Ors.*, in October 2012.

A RTI applicant, Girish Ramchandra Deshpande, had sought copies of all memos, show cause notices and censure/punishment awarded to a public servant. A.B. Lute. He had also sought other details such as his movable and immovable properties and details of his investments, lending and borrowing from banks and other financial institutions.

This was denied claiming exemption under Section 8(1)(j). This section exempts "information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information

Officer ... is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information: Provided that the information, which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature shall not be denied to any person."

A simple reading shows that under this clause, 'personal' can be denied if it has apparently no relationship to any public activity or interest; or the disclosure of the said information would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual.

The Court did not rule on whether the information was an outcome of a public activity or if its disclosure would amount to an unwarranted invasion of the privacy of the individual. It denied the information by reading only the first seven words of the provision and saying it was 'personal information'. Most information can be linked to some person. Realising that it may be difficult for public information officers and other appellate authorities to decide on what constitutes privacy, Parliament gave a simple test in the proviso – that information which would not be denied to Parliament or legislature would not be denied to any person. This can only have one meaning. That anyone claiming that information would be denied to the citizen would make a subjective statement that he would deny the information to Parliament.

It is well settled that literal interpretation should be given to a statute if the same does not lead to absurdity. In *Nasiruddin and others vs Sita Ram Agarwal* (2003) 2 SCC 577, the Court has stated: "37. The court's jurisdiction to interpret a statute can be invoked when the same is ambiguous... It cannot re-write or recast legislation. It is also necessary to determine that there exists a presumption that the legislature has not used any superfluous words. It is well settled that the real intention of the legislation must be gathered from the language used."

Girish Ramchandra Deshpande amends the RTI Act and has been used as a precedent in six subsequent Court judgments and has become the gold standard to convert RTI into an RDI, or Right to Deny Information. The Digital Personal Data Protection Act takes a cue from this and amends the RTI Act itself. There are other cases in which words in the law have not been accorded their usual meanings.

A call to citizens

To ensure that the RTI fulfils its original promise we should go by the original Act and not allow any distortions. Citizens and the media must take up the responsibility to discuss and defend it. Otherwise, we will have a dilution of our fundamental right under Article 19(1)(a) of the Constitution of India.

GS Paper 02 शासन

UPSC Mains Practice Question: सरकारी पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। (250 Words /15 marks)

संदर्भ :

- नौकरशाही प्रतिरोध, न्यायिक निर्णयों और विधायी संशोधनों के कारण आरटीआई अधिनियम की प्रभावशीलता कम होती जा रही है।

परिचय और प्रारंभिक आशा

- आरटीआई अधिनियम की शुरुआत ने सरकारी सूचना तक पहुँचने के उनके अधिकार को मान्यता देकर नागरिकों में आशा पैदा की।
- इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पारदर्शिता कानूनों में से एक माना गया, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार और मनमानी पर अंकुश लगाना था।
- नागरिकों से अपेक्षा की जाती थी कि वे सरकारी कार्यों पर सतर्कता निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करें।
- हालाँकि, समय के साथ, अधिनियम के कार्यान्वयन ने जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है, और लोकतांत्रिक जवाबदेही में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है।

सरकार की ओर से प्रारंभिक प्रतिरोध

- सरकार को जल्दी ही एहसास हो गया कि आरटीआई अधिनियम ने सत्ता को लोक सेवकों से नागरिकों के हाथों में स्थानांतरित कर दिया है।
- एक वर्ष के भीतर, अधिनियम को इस तरह से संशोधित करने का प्रयास किया गया जिससे यह कमजोर हो जाए। व्यापक सार्वजनिक विरोध के कारण इन संशोधनों को वापस लेना पड़ा।

आरटीआई तंत्र का क्षरण

- आरटीआई कार्यान्वयन के लिए अंतिम अपीलिय प्राधिकरण के रूप में सूचना आयोगों की स्थापना की गई।
- अधिकांश आयुक्त पदों पर सेवानिवृत्त नौकरशाहों को नियुक्त किया गया, जो नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए अनिच्छुक थे।
- चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और शासन में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता नहीं दी गई।
- कई आयुक्तों ने अपनी भूमिका को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के रूप में देखा और सीमित प्रतिबद्धता के साथ काम किया।

आरटीआई प्रक्रिया में देरी और अक्षमता

- हाई कोर्ट के न्यायाधीश प्रति वर्ष 2,500 से अधिक मामलों का निपटारा करते हैं, लेकिन आरटीआई आयुक्त बहुत कम मामलों का निपटारा करते हैं।
- आरटीआई मामलों की सरल प्रकृति को देखते हुए, प्रत्येक आयुक्त को आदर्श रूप से सालाना 5,000 से अधिक मामलों को संभालना चाहिए।
- कानून सरकारी विभागों के लिए 30-दिन की प्रतिक्रिया अवधि अनिवार्य करता है, लेकिन सूचना आयोगों के लिए कोई समय सीमा नहीं है।
- इससे बैकलॉग हो गया है, अक्सर प्रतिक्रियाओं में एक साल से अधिक की देरी होती है, जिससे सूचना प्राप्त होने तक अप्रासंगिक हो जाती है।
- नागरिक अक्सर विलंबित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे अधिनियम की प्रभावशीलता कमजोर होती है।

आरटीआई दंड प्रावधानों का कमजोर प्रवर्तन

- आरटीआई अधिनियम में सूचना देने से इनकार करने वाले अधिकारियों को दंडित करने के प्रावधान शामिल हैं।
- कई आयुक्त दंड लगाने में हिचकिचाते हैं, जिससे जवाबदेही की कमी होती है।
- सरकारें नए आयुक्तों की नियुक्ति में देरी करके, लंबित मामलों को बढ़ाकर इस प्रणाली को और कमजोर कर रही हैं।

न्यायिक व्याख्याएँ और उनका प्रभाव

- न्यायालयों ने फैसला सुनाया है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8 के तहत छूट की सख्ती से व्याख्या नहीं की जानी चाहिए।
- एक महत्वपूर्ण फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अंधाधुंध आरटीआई अनुरोध प्रशासन और राष्ट्रीय विकास में बाधा डाल सकते हैं।
- यह निर्णय इस धारणा के अनुरूप है कि आरटीआई का उपयोग समस्याग्रस्त है, जो अधिकारियों को अनुरोधों का जवाब देने से हतोत्साहित करता है।

व्यक्तिगत सूचना खंड का प्रभाव

- एक अन्य प्रमुख निर्णय ने सार्वजनिक अधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी तक पहुँच को प्रतिबंधित कर दिया।
- एक आरटीआई आवेदक ने एक लोक सेवक के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में विवरण मांगा था, लेकिन व्यक्तिगत सूचना छूट के तहत अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।
- न्यायालय ने यह जांच नहीं की कि क्या जानकारी सार्वजनिक गतिविधि से संबंधित थी या प्रकटीकरण सार्वजनिक हित में था।
- इस निर्णय ने एक महत्वपूर्ण प्रावधान को नजरअंदाज कर दिया जिसमें कहा गया था कि संसद को सुलभ जानकारी जनता को भी सुलभ होनी चाहिए।

- ▶ परिणामस्वरूप, इस निर्णय का उपयोग सूचना को अस्वीकार करने के लिए कई मामलों में मिसाल के तौर पर किया गया है।

विधायी परिवर्तनों पर चिंताएँ

- ▶ डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम ने सूचना तक पहुँच को प्रतिबंधित करके आरटीआई अधिनियम को और कमज़ोर कर दिया है।
- ▶ न्यायिक और विधायी परिवर्तनों की प्रवृत्ति आरटीआई को सूचना अस्वीकार करने के अधिकार (आरटीआई) में बदल रही है।

निष्कर्ष

- ▶ आरटीआई अधिनियम के मूल उद्देश्य को संरक्षित करने के लिए, नागरिकों और मीडिया को सक्रिय रूप से इसका बचाव करना चाहिए।
- ▶ सार्वजनिक सतर्कता के बिना, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मौलिक अधिकार कमज़ोर हो सकते हैं।